www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

आपका भरोसा, हमारी ताकत

RNI No. : DELHIN/2016/70240

2 राव की सोच की बुनियाद पर भारत बना...

3 चाइल्ड काउंसलर बनकर संवारें अपना भविष्य...

4 संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे जगद् गुरु...

वर्ष: 10 | अंक: 61 | दिल्ली, बुधवार, 24 दिसम्बर 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

पीएम मोदी से मिले नीरज चोपड़ा, पत्नी हिमानी मोर भी रहीं मौजूद

नई दिल्ली (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 23 दिसंबर को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास (7) से तस्वीरें साझा कीं, जहां उन्होंने भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर की मेजबानी की। तस्वीरों में प्रधानमंत्री खिलाड़ी के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत करते नजर आए और उन्होंने अपनी पोस्ट में कई विषयों, विशेष रूप से खेल से संबंधित विषयों पर चर्चा का उल्लेख किया। नीरज भारत के सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिहाज से 2025 का साल उनके लिए मिला-जुला रहा। उनके सीजन की एक बड़ी उपलब्धि दोहा डायमंड लीग में देखने को मिली, जहां उन्होंने 90 मीटर का बहुप्रतीक्षित आंकड़ा पार किया। 90.23 मीटर का उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, हालांकि यह स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर के बेहतर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे नीरज को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकूला दौरे पर

चंडीगढ़ (एजेन्सी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के पंचकूला दौरे को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती की पूर्व संध्या पर श्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकूला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण, जनकल्याणकारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन एवं निरीक्षण करेंगे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एमडीसी सेक्टर-1 स्थित अटल पार्क में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही वे अटल जी के जीवन एवं विचारों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे तथा एक विशाल रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर रक्तदाताओं को बैज पहनाकर प्रोत्साहित करेंगे।

'विकसित भारत-जी राम जी' से भारत के गांवों का कायाकल्प हो जाएगा: शिवराज सिंह चौहान

संजना भारती/पीआईबी

राजस्थान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में नागौर की मेड़ता सिटी में वृहद किसान सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तार्तरित की। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, किसान आयोग के अध्यक्ष सी. आर. चौधरी, सांसद सुमहिमा कुमारी, विधायक लक्ष्मण राम जी कलरू भी उपस्थित रहे।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान ने पिछले 2 साल में विकास का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 12,600 सड़कों के निर्माण के लिए 2 हजार 89 करोड़ रुपये की धनराशि आज जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं।

चौहान ने कहा कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। ज्यादा उपज देने वाले जलवायु अनुकूल नई किस्म के बीज का निर्माण प्रदेश में तेजी से हुआ है। साथ ही उत्पादन की लागत

कम करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,000 रुपये की धनराशि के साथ अतिरिक्त 3,000 रुपये की राशि देने का काम भी राज्य सरकार ने किया है। 9,000 रुपये की इसी राशि से किसान लाभांवित हुए हैं और कृषि उत्पादन की लागत में कमी आई है।

शिवराज सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व राजस्थान को 29 हजार करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कमियां थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया गया है। क्लेम में देरी करने पर बीमा कंपनियों को 12 प्रतिशत ब्याज सीधे किसानों के बैंक खातों में डालने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने एमएसपी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी दोगुना करने का काम किया गया है। इस साल केंद्र सरकार ने राजस्थान से लगभग 2 हजार 680 करोड़ रुपये की 3 लाख 5 हजार मीट्रिक टन मूंग खरीद को मंजूरी दी।

वही 5 लाख 54 हजार मीट्रिक टन मूंगफली खरीदने का काम भी किया जाएगा, 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन सोयाबीन भी खरीदने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होगी केंद्र सरकार किसानों को उचित दाम देगी और एमएसपी खरीद में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने नए बने विकसित भारत- जी राम जी कानून की भी चर्चा की और कहा कि विपक्ष इसकी बेवजह आलोचना करने में जुटा है, वास्तविकता यह है कि इस कानून से भारत के गांवों का कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बेहतरीन योजना का निर्माण हुआ है। इस योजना में मजदूरों का कल्याण और किसानों का ध्यान दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की साजिश रची जा रही है। चौहान ने कहा कि यूपीए काल में 40 हजार करोड़ से अधिक धनराशि मनरेगा पर खर्च नहीं की गई, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये तक प्रतिवर्ष मनरेगा के तहत खर्च किए गए और इस साल इसके लिए प्रस्तावित बजट राशि लगभग 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए कानून में ग्राम पंचायतों की बड़ी भूमिका है और इसलिए इस कानून के नाम में विकसित भारत जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतें ही अब गांव की विकास की योजना बनाएंगी। इस योजना के तहत एक विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव और रोजगार युक्त गांव बनाया जाएगा। गांव के लोग विकास की रुपरेखा तय करेंगे। 5 साल में करीब साढ़े 7 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत जल संरक्षण के काम प्राथमिकता के आधार पर करने का भी प्रावधान किया गया है।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की शिष्टाचार भेंट

अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली विस की पारदर्शिता एवं आधुनिकीकरण पहलों से कराया अवगत

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय शहरी विकास एवं विद्युत मंत्री, भारत सरकार मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अध्यक्ष ने मंत्री को दिल्ली विधान सभा की प्रस्तुति-शताब्दी-यात्रा, वीर विठ्ठलभाई पटेल शीर्षक पर विशेष रूप से प्रकाशित कॉफी टेबल बुक भेंट की। यह पुस्तक केंद्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष वीर विठ्ठलभाई पटेल को समर्पित है। यह प्रकाशन वर्ष 1925 से 2025 तक भारत की संसदीय यात्रा का दस्तावेजीकरण करता है तथा आधुनिक भारतीय संसदीय परंपराओं की नींव रखने वाले वीर विठ्ठलभाई झावेरीभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

भेंट के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएँ वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी के लिए कई नई योजनाएँ भी पाइपलाइन में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्रीय रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (आरआरटीएस) दिल्ली में परिचालित की जाएगी, जिससे पानीपत से करनाल तक की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। साथ ही, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कई पहलें योजनाबद्ध एवं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य शहरी गतिशीलता एवं क्षेत्रीय संपर्क को और बेहतर बनाना है। कॉफी टेबल बुक के विषय में बोलते हुए अध्यक्ष विजेंद्र

गुप्ता ने कहा कि यह कॉफी टेबल बुक भारत की विधायी एवं लोकतांत्रिक यात्रा के सौ वर्षों का समग्र दस्तावेज है। इस ग्रंथ में दुर्लभ अभिलेखीय छायाचित्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा उन निर्णायक क्षणों को संकलित किया गया है जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ से भारतीय लोकतंत्र को आकार दिया। पुस्तक का एक प्रमुख आकर्षण वर्ष 2025 में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का विस्तृत विवरण है, जिसका आयोजन केंद्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में श्री विठ्ठलभाई पटेल के निर्वाचन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया था।

श्री गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली विधान सभा द्वारा उठाए गए विभिन्न विकास कार्यों से भी अवगत कराया। इनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) का पूर्ण संचालन शामिल है, जिसके माध्यम से दिल्ली देश की पहली विधानसभा बनने की दिशा में अग्रसर है, जहाँ वास्तविक समय में ऑडिट निगरानी हेतु एक समग्र डिजिटल पोर्टल लागू किया गया है।

किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती सोना उगलती है: सीएम योगी

सीएम ने किसानों को दी ट्रैक्टर की चाबी, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी मेहनत को प्रणाम किया। सीएम ने किसान समृद्धि योजना के तहत ट्रैक्टर पाने वाले किसानों के चेहरे की चमक का जिक्र किया। बोले कि कोई किसान अपनी मां तो कोई पत्नी को ट्रैक्टर में बिठाकर ले जा रहा है। यही किसान की ताकत होती है, सर्दी, गर्मी की परवाह किए बिना जब वह पसीना बहाता है और सर्दी को अपनी अस्थियों में समाहित कर ऊर्जा का प्रवाह धरती मां के साथ करता है तो खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर विधान भवन प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सीएम ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी। साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों, एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ के प्लॉट आवंटन प्रक्रिया का बटन दबाकर शुभारंभ किया।

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत से किसानों ने प्रगति की

है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब पहली बार किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना। धरती हमारी मां और हम सभी इसके पुत्र हैं, इसलिए पुत्र का दायित्व है कि जब मां बीमार या संकट में हो तो पुत्र उसे संकट से उबारने में योगदान देता है। पहली बार स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से पीएम मोदी ने 2014 में धरती मां की सेहत के बारे में हर किसी को जागरूक किया। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से जोड़ा, फिर एक-एक करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या बीज से लेकर बाजार तक किसानों की सुविधाओं को बढ़ाया गया।

सीएम योगी ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों का मान बढ़ाया। लघु व सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण मोचन कार्यक्रम लागू किया। पहले किसान शासन की किसी भी योजना का अंग नहीं था, लेकिन आज किसान को शासन की हर योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज बिचौलिया किसानों की फसल का दाम नहीं तय करता। यदि किसान को बाजार में फसल का अच्छा दाम मिला तो ठीक वरना सरकार उसे खरीदेगी। यूपी के अंदर धान, गेहूं, चना, सरसो, बाजरा, मक्का आदि फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और लागत कम हुई है। यही किसानों की समृद्धि का आधार है।

सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह के वक्तव्य का जिक्र किया। वे हमेशा देश, गांव व किसान के हित में काम करते थे। वे कहते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारत की समृद्धि का मार्ग देश के खेत व खलिहान से होकर गुजरता है। जागरूक जनशक्ति ही सफल लोकतंत्र का आधार है। यूपी सरकार में उन्हें जब मौका मिला तो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया। जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बंद करने के लिए मंडी अधिनियम पारित कराया। पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु-सीमांत किसानों के साढ़े तीन एकड़ तक के भूखंड को भूराजस्व के भुगतान में छूट भी दिलाई। उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरूआत भी की। कृषि व ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

सीएम योगी ने कहा कि 1996 से 2017 (21-22 वर्ष) में किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, उससे लगभग 75 हजार करोड़ रुपये अधिक धनराशि 8 वर्ष में किसानों के खाते में डाली है। अभी हाल में ही गन्ना मूल्य का दाम बढ़ाया है। पेराई सत्र 2025-26 में अगेती गन्ना 400 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। सीएम ने कहा कि यूपी में किसान समृद्धि की तरफ अग्रसर हुआ है। किसानों ने नई तकनीक और अच्छी क्वालिटी के बीज पर ध्यान दिया तो कम लागत में अच्छा उत्पादन कर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा कि 8 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। यूपी में इनकी संख्या अब 89 हो गई है। 9 क्लाइमेटिक जोन में इतने कृषि विज्ञान केंद्र किसी राज्य में नहीं हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक

संजना भारती ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन बदायूँ। अपर जिलाधिकारी, प्रशासन अरुण कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय बाल विवाह मुक्त भारत संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें अपर जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2025 को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में बीर वाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से किया जाएगा उन्होंने अवगत कराया कि दिनांक 18 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 25 के मध्य विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधि आयोजित कर बच्चों में साहस एवं राष्ट्र प्रेम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सकारात्मक नागरिकता के मूल्यों को सुधार किया जाना अपेक्षित है जिसके क्रम में दिनांक 26 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उक्त कार्यक्रम के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन में कठिन परिस्थितियों में सड़क पर मिलने वाले अनाथ परित्यक्त या आपात स्थिति में

रहे लोगों का जनपद स्तर पर रेस्क्यू किए जाने हेतु गठित समिति के द्वारा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से अभियान चलाया जायेगा तथा मिलने वाले बच्चों एवं महिलाओं को यथासंभव परिवार में पुनर्वासित करने अथवा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थानों एवं महिला आश्रय गृहों में आवासित कराए जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए, इस संबंध में चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पुलिस विभाग और नगर निकाय विभाग तथा श्रम विभाग को भी निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि जनपद में ऐसे इन स्थानों का चिन्हांकन किया जाए जहां ऐसे परिवार, बच्चे अथवा महिलाएं मिलने की संभावनाएं हो तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 के मध्य बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई जिसके अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन जनपद स्तर पर किया जा रहा है जिसका उद्देश्य बाल विभाग की घटनाओं को रोकना समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता का वातावरण विकसित करना तथा कानून के प्रभावी क्रियावन के माध्यम से बालिकाओं एवं बालकों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा करना है जिसके संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट एवं चाइल्ड हेल्पलाइन को निर्देशित किया गया कि उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु धर्मगुरु, समुदाय में बैठक करें और विद्यालय, कॉलेज स्तर आदि पर कार्यक्रम करना सुनिश्चित करें।

खानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय किसान गोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन

संजना भारती संवाददाता
अर्जुन कुमार झा

समस्तीपुर। खानपुर प्रखंड स्तरीय किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका शुभारंभ संयुक्त रूप से बीस सूत्री अध्यक्ष सह सासंद प्रतिनिधि रामनारायण सिंह, प्रखंड किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष संजीव चौधरी, जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह, बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय कुशवाहा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीव कुमार चौधरी के द्वारा की गई जबकि संचालन सुशील कुशवाहा एटीएम के द्वारा किया गया। कृषि वैज्ञानिक केवीके बिरौली से आए हुए सुमित कुमार के द्वारा किसानों को जलवायु अनुकूल खेती के बारे में, जैविक खेती, कीटनाशक, बीज उपचार, रब्बी मौसम में सभी फसलों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बीस सूत्री अध्यक्ष के द्वारा व्यवसायिक रूप से खेती करने पर जोर दिया गया। जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह के द्वारा बीज वितरण उर्वरक वितरण में पारदर्शिता के बारे में बतलाया गया। वही बीजेपी मंडल अध्यक्ष के द्वारा कृषि विभाग के सभी कर्मी पंचायतों में उपस्थित रह कर योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सभी सदस्यगण जनप्रतिनिधिगण अन्न दाता किसान भाइयों ने भाग लिया।

मौके पर तकनीकी प्रबंधक सह सचिव सूरज सहनी, कृषि समन्वयक अजय मिश्रा सभी किसान सलाहकार कन्हैया चौधरी, ललित सहनी, निरंजन कुमार, उमेश मांझी, रामबाबू राम, एटीएम शशि भूषण कुमार सुशील कुशवाहा सहित पंकज कुमार राय, श्रवण कुमार सिंह, रामश्रेष्ठ सिंह, ब्रह्मदेव रॉय, सुनील महतो, पांचू राम, अजय यादव, रौशन कुमार सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा

नई दिल्ली (एजेन्सी)। देशभर में सुशासन के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, 25 दिसंबर को "सुशासन दिवस" के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित होकर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने नागरिकों के सर्वांगीण कल्याण के उद्देश्य से कई पहलें शुरू की हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल है मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पहार योजना, जो पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करके बच्चों की शिक्षा को सशक्त बनाती है। वर्तमान में, गुजरात भर में 4 लाख से अधिक छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ पोषण के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन के साथ-साथ यह पहल ताजा और पौष्टिक नाश्ता प्रदान करती है।

ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया

एसबी ब्यूरो

तेघड़ा(बेगूसराय)। अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा बेगूसराय सह जानकी ब्रह्मर्षि विवाह एवं उपनयन समिति के तत्वावधान में मंगलवार को तेघड़ा के एक निजी होटल में बेगूसराय ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वाचन संत शिरोमणि गोपाल कुमार जी एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। यह सम्मेलन समाज का कल्याण पीड़ितों की सेवा के लिये किया गया है।

अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि समाज के गरीब कमजोर लोगों की बेटी की शादी और उपनयन संस्कार समिति अपने खर्च पर करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेन्द्र सिंह एवं मंच संचालन डॉ. सच्चिदानंद पाठक ने किया।

इस अवसर पर महासचिव रामबाबू सिंह, अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, अवकाश

प्राप्त डीएसपी सुनील कुंवर, कार्यक्रम के प्रायोजक राम निवास सिंह, रामकिंकर सिंह, राजकिशोर शर्मा, डॉ. जितेन्द्र राय, कार्तिक प्रसाद सिंह, रमेश सिंह, समाजसेवी अंजनी कुमार, वरिष्ठ लेखक महेश भारती, सुमंत कुमार पूर्व मुखिया, मुखिया राममूर्ति चौधरी, बुलन चौधरी उर्फ राघवेन्द्र चौधरी, राजेश कुमार, कन्हैया चौधरी, सरोज कुमार राय, राजीव कुमार वत्स आदि उपस्थित थे।

सम्पादकीय

बांग्लादेश की स्थिरता भारत के लिए जरूरी

पिछले साल शेख हसीना सरकार के गिरने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कड़वाहट और अविश्वास इतना अधिक बढ़ गया है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल वीजा सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इस आग में घी डालने का काम दोनों देशों में बैठे कट्टरपंथी नेता कर रहे हैं। पड़ोस में कट्टर दुश्मन की तरह एक पाकिस्तान हमारे लिए मानो काफी नहीं था कि अब बांग्लादेश के साथ संबंध भी उसी नफरत की राह पर बढ़ रहे हैं। ऐसे में 1971 में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की भारत को पस्त होते और चौतरफा घिरे देखने की जो हसरत पूरी नहीं हुई थी, उसे अब पूरी करने की कोशिशें हो रही हैं। सोमवार को भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर से मोहम्मद यूनुस की फोन पर करीब आधे घंटे तक बात हुई। जिसमें यूनुस ने भारत में शरणागत शेख हसीना पर नए आरोप लगाए कि हसीना के समर्थक कथित तौर पर चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और उनकी फरार नेता विद्रोह से हिंसा भड़का रही हैं। बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश में मृत्युदंड मिला है और वह उनका प्रत्यर्पण चाहता है। लेकिन भारत इसकी अनुमति नहीं दे रहा। वहीं यूनुस पर बार-बार आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव टालना चाहते हैं, लेकिन यूनुस ने अमेरिका को बताया कि चुनाव अगले साल 12 फरवरी को समय पर होंगे। अमेरिकी दूत के साथ चर्चा में शेख हसीना पर चुनाव रोकने का इल्ज़ाम लगाकर शायद इस बात की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि उनकी पार्टी अवामी लीग चुनावों से बाहर रहे। ध्यान रहे कि भारत ने हाल ही में कहा है कि वह बांग्लादेश में 'शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों' के पक्ष में है। इसमें समावेशी का मतलब चुनाव प्रक्रिया में हसीना की अवामी लीग को भी शामिल करना है। लेकिन बांग्लादेश सरकार ने अपने बयानों में 'समावेशी शब्द का उल्लेख नहीं किया है। उसने कहा है कि वह सर्वोच्च मानकों वाले चुनाव कराना चाहती है, जिनका पिछले 15 सालों से अभाव रहा है। यानी फिर से शेख हसीना को निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि हम यह नहीं चाहते कि पड़ोसी देश हमें यह सलाह दे कि बांग्लादेश में चुनाव कैसे कराए जाने चाहिए। बांग्लादेश को बेशक अपनी संप्रभुता के लिए बोलने का हक है, लेकिन उसे भू राजनैतिक परिस्थितियों पर भी गौर करना चाहिए। बांग्लादेश की 94 प्रतिशत सीमा भारत से लगती है। एक देश की उथल-पुथल दूसरे को भी प्रभावित करती है, इसलिए 4,000 किलोमीटर की साझा सीमा पर सुरक्षा और शांति दोनों देशों के लिए जरूरी है। बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। सुरक्षा और व्यापार के मामले में वह भारत पर निर्भर है। वहीं बांग्लादेश से भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों में सस्ते और सुलभ संपर्क में मदद मिलती है। पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है। बांग्लादेश की राजनैतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसी बहाने एक तरफ पाकिस्तान और चीन और दूसरी तरफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश इसमें अपने दखल का मौका तलाश रहे हैं। पिछले हफ्ते ही भारत विरोधी कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पश्चिमी देशों ने शोक प्रकट किया, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक युवा दीपू दास की मॉब लिंचिंग और नृशंस हत्या पर मौन धारण किया। अभी बेशक संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह की हिंसा रोकने का आह्वान किया है, वहीं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के दो सदस्यों राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने भी ढाका में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों को चिंताजनक कहा है। लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तो दीपू दास की लिंचिंग को अल्पसंख्यकों पर हमले के रूप में पेश किए जाने को ही खारिज कर दिया है। इस बीच अकेले रूस ने फिर से भारत का साथ दिया है। बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरियेविच खोजिन ने कहा है कि रूस दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन उनका मानना है कि यह समझदारी होगी कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे तनाव और न बढ़े। बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत के साथ तनाव कम करेगा, उतना दोनों देशों और पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही खोजिन ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को याद करते हुए कहा कि 1971 में बांग्लादेश को आजादी मुख्य रूप से भारत की मदद से मिली थी। रूस ने भी समर्थन किया था। रूसी राजदूत का यह बयान भारत के लिए काफी अहम है। क्योंकि इस समय भी पश्चिमी देश बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी), जमात-ए इस्लामी या इंकलाब मंच के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिनका रुख अमूमन भारत विरोधी है। बल्कि उस्मान हादी का इंकलाब मंच तो सीधे-सीधे बांग्लादेश के इस्लामीकरण के पक्ष में है। ऐसे में रूस का फिर से भारत के साथ खड़े होना एक भरोसेमंद दोस्त के आश्वासन जैसा है, जिसके भारत को रूस का शुक्रगुजार होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंसा और अशांति के बीच बीएनपी ने कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की 25 दिसंबर को वतन वापसी हो रही है। तारिक रहमान बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और अध्यक्ष खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं, उन्हें साल 2007 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, साल 2008 में वो इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे और अब 17 साल बाद चुनावों से पहले वापस लौट रहे हैं। बीएनपी अभी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है और कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में वो सत्ता में आ सकती है।

जयंती

भोगराजू पट्टाभि सीतारामैया

जन्म-24 दिसम्बर, 1880, आन्ध्र प्रदेश; मृत्यु-17 दिसम्बर, 1959) भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गाँधीवादी और पत्रकार थे। इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की अलख जगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने राष्ट्रीय हितों को दूसरे हितों के मुकाबले हमेशा प्राथमिकता में रखा। सीतारामैया राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। जब सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पट्टाभि सीतारामैया सुभाषचन्द्र बोस से पराजित हो गए, तब महात्मा गाँधी ने उनकी हार को अपनी हार कहा था। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1952 से 1957 तक वे मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे थे। सीतारामैया एक लेखक के तौर पर भी जाने जाते थे। उन्होंने 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' का इतिहास भी लिखा था।

पुण्यतिथि

एम. जी. रामचन्द्रन

जन्म: 17 जनवरी, 1917; मृत्यु: 24 दिसम्बर, 1987) तमिल फि ल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, फि ल्म निमार्ता-निर्देशक थे जो बाद में राजनीति में आये और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1977 से लेकर 1987 में उनके निधन तक वे भारत के तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री रहे। एम.जी.आर. का जन्म कैन्डी, श्रीलंका में हुआ था।

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHI/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

राव की सोच की बुनियाद पर भारत बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था की उछाल इन दिनों दुनिया देख रही है। लेकिन पिछली सदी के अस्सी के दशक में अर्थव्यवस्था बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी थी। हालात इतने बुरे थे कि भारत को अपना रिजर्व सोना बैंक ऑफ इंगलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। राव से ठीक पहले प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा, जीवन जैसा जिया में इस गिरवी प्रकरण की पूरी जानकारी दी है

-उमेश चतुर्वेदी

पामुलपार्थी वेंकट नरसिंह राव...यही पूरा नाम था उनका। आज ही के दिन ठीक इक्कीस साल पहले उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आखिरी सांस ली थी, जिसे देश के सबसे बेहतरीन सार्वजनिक अस्पताल माना जाता है। एम्स के नाम से विख्यात इस अस्पताल में जब उनकी आत्मा उनके शरीर रूपी पिंजरे से उड़ गई, तब देश में उन डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासन था, जिन्हें उन्होंने ही राजनीति की दुनिया में प्रवेश कराया था। राव कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण विदाई के हकदार थे। लेकिन उनकी ही पार्टी ने उन्हें यह विदाई मयस्सर नहीं होने दी और देश का प्रधानमंत्री भी मौन व्रत धारण किए रह गया। नेहरू, इंदिरा और राजीव को भारत रत्न देने वाली कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार ने अपने ही उस राव को उचित सम्मान देना उचित नहीं समझा, जिसके वे अध्यक्ष रह चुके थे।

भारतीय अर्थव्यवस्था की उछाल इन दिनों दुनिया देख रही है। लेकिन पिछली सदी के अस्सी के दशक में अर्थव्यवस्था बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी थी। हालात इतने बुरे थे कि भारत को अपना रिजर्व सोना बैंक ऑफ इंगलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। राव से ठीक पहले प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा, जीवन जैसा जिया में इस गिरवी प्रकरण की पूरी जानकारी दी है। चंद्रशेखर के बाद एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बने राव के सामने तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुरी गत की जानकारी दी तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। ऐसे हालात में उनका विचलित होना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रोफेशनल अर्थशास्त्री को देश का वित्त मंत्री बनाने की सोची। उन्हें तब दो नाम सुझाए गए थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके आईजी पटेल और मनमोहन सिंह। राव की पहली पसंद पटेल थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमार और बुजुर्ग मां की देखभाल के चलते वह जिम्मेदारी भरा पद लेना स्वीकार नहीं किया। नियति मनमोहन सिंह के पक्ष में थी। मनमोहन वित्त मंत्री बने। 1991 की 25 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करते हुए मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया। आर्थिक मोर्चे पर जारी लाइसेंस राज की विदाई की शुरूआत हुई। आर्थिक खुलेपन ने देश की आर्थिकी की जो नींव रखी, आज उसी नींव पर आगे बढ़ते हुए देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था का गौरव हासिल कर चुका है। बेशक यह सब मनमोहन सिंह की बदौलत हुआ। लेकिन अगर उनकी पीठ पर नरसिंह राव का हाथ नहीं होता तो क्या वे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यवस्था के साथ कदमताल करने के लिए उद्यत हो सकते थे? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। भारत की आर्थिकी को मजबूत बुनियाद देने के साथ ही वैश्विक व्यवस्था के साथ कदमताल के लिए तैयार करने में मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन बिना नरसिंह राव के मजबूत समर्थन के, वे ऐसे कदम नहीं उठा सकते थे। आज भारत की आर्थिकी की जो वैश्विक चमक दिख रही है, उसके असर नींव निर्माता नरसिंह राव ही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस कांग्रेस के वे नेता रहे, जिस कांग्रेस क साथ उन्होंने अपनी समूची राजनीतिक यात्रा पूरी की, उस कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। किनारा करने की वजह रहा बाबरी विध्वंस। छह दिसंबर 1992 को बाबरी का ध्वंस हुआ। ऐसा नहीं कि नरसिंह राव ने ध्वंस को रोकने की तैयारी नहीं की थी। गांधी-नेहरू परिवार के नजदीकी रहे पूर्व विदेश सेवा अधिकारी और कांग्रेसी राजनेता मणिशंकर अय्यर राव को इसी वजह से भाजपा का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं। बाबरी विध्वंस के बाद वामपंथी बौद्धिकों के एक खेमे ने उन्हें खाकी निक्कर वाला कहना शुरू कर दिया था। यहां याद दिलाना जरूरी है कि खाकी निक्कर कुछ साल पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की गणवेश होती थी। लेकिन नरसिंह राव ने अपने उपर लगे आरोपों का पुस्तक लिखकर जवाब दिया है. जो 2004 में उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई है। अयोध्याः छह दिसंबर नामक यह पुस्तक साल 2006 में प्रकाशित हुई। इस किताब में एक तरह से राव ने बाबरी ध्वंस को लेकर उन पर लगने वाले अकर्मण्यता के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है। इसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन और उससे पहले की घटनाओं, अपनी कार्रवाइयों और तब के राजनीतिक दबावों को लेकर पूरी जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में वे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा पाए। उन्होंने बताया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं थी और उनके सामने कई संवैधानिक चुनौतियां और बाधाएं भी थीं। इन तथ्यों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों मस्जिद को बचाने की उनकी कोशिशें किस तरह नाकाम रहीं। विनय सीतापति ने हाफ लायन नाम से राव की जीवनी लिखी है। इस पुस्तक में वे भी तमाम तथ्यों से साबित करने में सफल रहे हैं कि राव चाहकर भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे। अपनी किताब में राव ने तफसील से बताया है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अयोध्या पहुंच रहे कारसेवक शांतिपूर्ण हैं। राव ने साथ ही यह भी बताया है कि तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मस्जिद की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। ऐसे में संवैधानिक मयार्दाओं और संघीय ढांचे के संवैधानिक प्रावधानों के कारण उनके हाथ बंधे हुए थे। राव ने अपनी पुस्तक में राम मंदिर आंदोलन के पीछे की राजनीतिक चालों और धार्मिक भावनाओं के दोहन के खतरों पर भी प्रकाश डाला गया है।

इसमें दो राय नहीं कि बाबरी ध्वंस के बाद कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह बदल गई। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान की जातीय कीमियागिरी के दम पर लंबे समय तक शासन में रही कांग्रेस का समर्थक आधार छीजने लगा। अल्पसंख्यकों ने कई प्रमुख राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से किनारा कर लिया। इसका असर कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति पर पड़ा। जिस समय बाबरी ध्वंस हुआ, उस समय गांधी-नेहरू परिवार राजनीति से दूर था। सोनिया गांधी तो सक्रिय राजनीति में 1998 में आईं। लेकिन उनके इशारे पर कांग्रेस का एक बड़ा खेमा काम करता रहा। अर्जुन सिंह, प्रियरंजन दास मुंशी, मणिशंकर अय्यर, प्रणब मुखर्जी आदि कांग्रेसी प्रथम परिवार के इशारे पर काम करते रहे। जब 1996 में कांग्रेस संसदीय चुनावों में हार गई तो नरसिंह राव को इस खेमे ने ना सिर्फ अप्रासंगिक बनाना शुरू किया, बल्कि उन्हें महत्वहीन भी बना दिया। कांग्रेस पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 19884 में हुए सिख विरोधी हिंसा का भी दाग है। दिलचस्प यह है कि उस वक्त राजीव सरकार के गृहमंत्री नरसिंह राव ही थे। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। क्योंकि उसके साथ राजीव गांधी का वह बयान चिपका हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा से ग्रस्त पंजाब को पटरी पर लाने वाले नरसिंह राव ही थे। नरसिंह राव ने ही लुक ईस्ट नीति शुरू की और एशियायी देशों से भारत के मजबूत संबंध बनाने शुरू किए थे। लेकिन उनके इन योगदानों को भुला दिया गया। राव सिर्फ भारतीय आर्थिकी के ही शिल्पकार नहीं थे, बल्कि देश के आतंकग्रस्त इलाकों को सख्त प्रशासन और विकास कार्यों के समायोजन के जरिए मुख्यधारा में जोड़ने वाले रचनाकार भी रहे। मोदी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि उसने राजनीतिक कारणों से राव को 2024 में भारत रत्न दिया। लेकिन यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि राव का सम्मान भारत के बदलाव का दौर शुरू करने वाले शिल्पी का सम्मान है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

मुक्त व्यापार के लिए खतरा बन गए हैं ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति की अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियां, जो मनमानी टैरिफ, अन्य देशों को अपने विरोधियों के साथ व्यापार का बहिष्कार करने के लिए मजबूर करने और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली की पूरी तरह से अनदेखी करने की विशेषता है, पहले ही महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार व्यवधान और अनिश्चितता पैदा कर चुकी है। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और पूवार्नुमेयता के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं

-नन्तू बनर्जी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को रूस, वेनेजुएला और कई अन्य देशों से समस्याएं हो सकती हैं और उन देशों से निपटने के लिए अमेरिकी व्यापार और राजनयिक नीतियों पर फैसला करने का उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन उन्हें अन्य स्वतंत्र देशों पर अपनी पसंद, नापसंद और पूर्वाग्रह थोपने का कोई अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य से वह ठीक वैसा ही कर रहे हैं।

ट्रम्प प्रशासन ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को कमजोर कर दिया है, जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और विवादों में मध्यस्थता करने के लिए स्थापित निकाय है। अमेरिका नेडब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को रोक दिया है, जिससे 2019 के अंत से व्यापार विवादों पर बाध्यकारी फैसले जारी करने की उसकी क्षमता प्रभावी रूप से पंगु हो गई है। इससे अन्य देशों को वैकल्पिक, अंतरिम मध्यस्थता व्यवस्था बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियां, जो मनमानी टैरिफ, अन्य देशों को अपने विरोधियों के साथ व्यापार का बहिष्कार करने के लिए मजबूर करने और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली की पूरी तरह से अनदेखी करने की विशेषता है, पहले ही महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार व्यवधान और अनिश्चितता पैदा कर चुकी है। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और पूवार्नुमेयता के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। तेल समृद्ध वेनेजुएला के खिलाफ ट्रम्प की राजनयिक और व्यापार नीतियों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से वेनेजुएला में आने और जाने वाले सभी स्वीकृत तेल टैंकरों की नौ सैनिक नाकाबंदी करके कई देशों और उसके प्रमुख व्यापार भागीदारों जैसे चीन, ब्राजील, तुर्की, कोलंबिया और भारत को मुश्किल में डाल दिया है। वेनेजुएला का व्यापार मुख्य रूप से एशिया और यूरोप को तेल निर्यात और भोजन, प्रौद्योगिकी और मशीनरी के आयात पर निर्भर है। ट्रम्प की नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा के बाद एशियाई व्यापार में अमेरिकी कच्चे तेल वायदा एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर $55.96 प्रति बैरल हो गया। पिछले हफ्ते तेल की कीमतें $55.27 प्रति बैरल पर बंद हुईं, जो फरवरी 2021 के बाद सबसे कम बंद भाव था। वेनेजुएला के कच्चे तेल के एक प्रमुख खरीदार, भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीजने उस देश से तेल आयात बंद कर दिया है। हाल ही में, रिलायंस ने 20 नवंबर से जामनगर में अपनी निर्यात-केंद्रित एसईजेडरिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का आयात भी बंद कर दिया है, ताकि रूसी तेल से बने उत्पादों पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का पालन किया जा सके, और जनवरी 2026 की समय सीमा से पहले अपने वैश्विक निर्यात बाजार के लिए गैर-रूसी कच्चे तेल की ओर रुख किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के बजाय द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे एक अनुमानित, नियमों पर आधारित व्यवस्था की जगह एक शक्ति आधारित प्रणाली आ रहा है, जहां बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा दबाव डाल सकती हैं। इस रवैये से अमेरिका अपने कई सहयोगियों की नजर में कम भरोसेमंद पार्टनर बन गया है। अमेरिकी नीति से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता आ रही है क्योंकि वह लगातार व्यापार नीतियों में बदलाव कर रहा है और नए टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल करके बाजार में अस्थिरता पैदा कर रहा है, जिससे व्यवसायों के लिए लंबी अवधि की योजना बनाना मुश्किल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था कई प्रतिस्पर्धी व्यापार गुटों में बंट सकती है, जिससे 1930 के दशक जैसी आर्थिक अराजकता पैदा हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप के तहत अमेरिका का नया रवैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यापार प्रणाली को मौलिक रूप से चुनौती देता है और उसे बाधित करता है।

नवीनतम अमेरिकी नीति ने 2025-26 के लिए वेनेजुएला से भारत के नियोजित तेल आयात को पूरी तरह से अनिश्चित और अस्थिर बना दिया है, जो इस साल की शुरूआत में 250,000 बैरल प्रति दिन से ज्यादा की उच्च मात्रा से मार्च 2025 में लगाए गए नए अमेरिकी टैरिफ (वेनेजुएला का तेल खरीदने वाले देशों पर 25 प्रतिशत) के कारण काफी कम हो गया है, जिससे प्रमुख भारतीय रिफाइनर रिलायंस को खरीदारी रोकनी पड़ी है। भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 90 प्रतिशत आयातित तेल पर निर्भर है, रूसी तेल व्यापार पर पश्चिमी प्रतिबंधों की भरपाई के लिए ईरान और वेनेजुएला जैसे विविध ऊर्जा स्रोतों की लगातार तलाश कर रहा है। इससे जटिल भू-राजनीतिक कारकों के बीच भविष्य की विशिष्ट मात्रा का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। ईरान से भारत की 2026 की तेल आयात योजनाओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है क्योंकि वे भू-राजनीतिक बदलावों, विशेष रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों पर निर्भर करती हैं। भारत ने अमेरिका से कहा है कि अगर वह कीमतों में बढ़ोतरी से बचने के लिए रूसी आयात में काफी कटौती करता है तो उसे ईरानी (और वेनेजुएला के) तेल की जरूरत होगी। भारत वर्तमान में अमेरिका से बहुत सारा तेल आयात कर रहा है, हालांकि ईरान अनुकूल छूट और क्रेडिट शर्तें दे रहा है जिसका भारत लाभ उठाना चाहता है। भारत किसी भी स्रोत से सस्ता तेल चाहता है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा है, लेकिन स्वीकृत आपूर्तिकताओं के लिए अमेरिकी मंजूरी पर निर्भर करता है, जिससे 2026 अनिश्चित हो गया है। भारत किफायती तेल की तलाश में है, संभावित रूप से स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी, रूसी और ईरानी आपूर्ति को संतुलित कर रहा है। इस साल अमेरिका से भारत का कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ गया, जो अक्टूबर के आसपास लगभग 568,000 से 575,000 बैरल प्रति दिनके रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पारंपरिक आपूर्तिकताओं पर निर्भरता कम करने और अमेरिकी ऊर्जा पहलों के साथ तालमेल बिठाने की भारत की रणनीति को दशार्ता है। 2026 में, अमेरिका से भारत की तेल आयात योजना ज्यादातर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर फोकस करता है। देश की पब्लिक सेक्टर की ऑयल रिफाइनरियों ने आने वाले साल में लगभग 22 लाख टन एलपीजी आयात करने पर सहमति जताई है। यह अमेरिका के साथ भारत के पहली बार के समझौते में भारत की कुल एलपीजी जरूरतों का लगभग 10 प्रतिशत पूरा करता है।

ट्रम्प अभी भी खुश नहीं हैं। उन्हें और चाहिए। ट्रम्प प्रशासन अपने सहयोगियों के साथ-साथ विरोधियों पर भी अमेरिका से ज्यादा खरीदने के लिए काफी दबाव डाल रहा है। दूसरे डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की व्यापार और टैरिफ में गड़बड़ी के कारण दुनिया भर के व्यापर साझेदार अपनी आर्थिक नीतियों और आपूर्ति श्रृंखला पर फिर से विचार कर रहे हैं। वैश्विक विकास को लेकर अनिश्चितता के कारण, पूंजी बाजार में अस्थिरता से अंदरूनी निवेश में कमी आ सकती है और नकद पर दबाव पड़ सकता है। ऊर्जा क्षेत्र, जो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ भारत और चीन जैसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, कई तरह के जोखिमों का सामना कर रहा है। अमेरिकी शेल तेल की प्रतिस्पर्धा से ऑर्गनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंगकंट्रीज (ओपेक प्लस)के उत्पादन तालमेल पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, वैश्विक व्यापार मार्ग में खाड़ी समुद्री तंग बिंदु से कोई भी बदलाव क्षेत्रीय परिवहन राजस्व पर असर डाल सकता है। समान टैरिफ, पारस्परिक कर और प्रमुख आयात पर प्रतिबंध जैसे उपायों के जरिए व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से, जिससे जवाबी कार्रवाई और जटिल वैश्विक व्यापार बातचीत हो रही है, राष्ट्रपति ट्रम्प टैरिफ और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की योजना बना रहे हैं ताकि चीन, भारत, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों को अपनी व्यापार नीतियों और उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूर किया जा सके। इसने वेनेजुएला के भारत के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने के प्रयास का कड़ा विरोध किया है, ऐसे समय में जब दक्षिण अमेरिकी देश ने पारंपरिक तेल व्यापार से परे संबंधों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है। अमेरिका अपने आर्थिक एजंडे को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड और टैरिफ का दबाव डाल रहा है। नतीजतन, भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं इस स्थिति से निपटने के लिए द्विपक्षीय व्यापार सौदों का विकल्प चुन रही हैं।

अमेरिका में नई फाइलें जारी, रेडैक्शन और गायब दस्तावेजों पर विवाद

(एजेन्सी)।

अमेरिका के न्याय विभाग ने दिवंगत यौन अपराधी और फाइनेंसर जेफ्री एप्स्टीन से जुड़े हजारों अतिरिक्त दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन फाइलों में कई प्रभावशाली और चर्चित हस्तियों की तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनके साथ एप्स्टीन के संपर्क होने की पुष्टि होती हैं। बता दें कि यह दस्तावेज एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किए गए हैं, जिसे नवंबर में कांग्रेस से पारित होने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून का रूप दिया था। इस कानून के अनुसार, सरकार को एप्स्टीन और उसकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल से जुड़े सभी गैर-गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने थे। मैक्सवेल फिलहाल यौन तस्करी मामले में 20 साल की सजा काट रही हैं। हालांकि, इन फाइलों के सामने आने के बाद पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में दस्तावेजों को भारी तौर पर ब्लैकआउट यानी रेडैक्ट किया गया है, जिससे कई अहम जानकारियां पढ़ी ही नहीं जा सकती हैं। अभियान चला रहे संगठनों का कहना है कि इससे सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ पा रही हैं।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जारी की गई फाइलों में से कम से कम 16 दस्तावेज बाद में वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। इनमें एक तस्वीर ऐसी भी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे थे। इस हटाए जाने को लेकर न्याय विभाग ने अब तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, हालांकि सोशल मीडिया पर विभाग ने कहा है कि सामग्री की कानूनी समीक्षा और आवश्यक रेडैक्शन की प्रक्रिया जारी हैं। गौरतलब है कि एप्स्टीन ने 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में आत्महत्या कर ली थी। उससे पहले भी उससे जुड़े कई दस्तावेज और अदालत के रिकॉर्ड सामने आ चुके थे। इस बार जारी हुई फाइलों में एक अहम खुलासा यह है कि एफबीआई को एप्स्टीन के अपराधों की जानकारी उसकी पहली गिरफ्तारी से करीब एक दशक पहले मिल चुकी थी। वर्ष 1996 में पीड़िता मारिया फार्मर ने एफबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। नई फाइलों में ग्रैंड जूरी की गवाही भी शामिल है, जिसमें नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण और पैसों के बदले यौन कृत्यों के विवरण दर्ज हैं। कुछ बयान बताते हैं कि पीड़िताओं की उम्र 14 साल तक थी। एक गवाह ने यह भी कहा कि वह खुद 16 साल की उम्र में एप्स्टीन के संपर्क में आई और बाद में अन्य लड़कियों को लाने के लिए उसे पैसे दिए जाते थे।

इन दस्तावेजों के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें बिल क्लिंटन, मिक जैगर, माइकल जैक्सन, डायना रॉस, केविन स्पेसी, रिचर्ड ब्रैनसन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि, न्याय विभाग ने इन तस्वीरों के संदर्भ या परिस्थितियों को लेकर कोई आधिकारिक विवरण नहीं दिया।

पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रवक्ता ने इन तस्वीरों को भटकाने वाला बताते हुए कहा है कि क्लिंटन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा और वे एप्स्टीन से काफी पहले ही संबंध तोड़ चुके थे। वहीं, ट्रंप से जुड़ी फाइलों को लेकर व्हाइट हाउस का कहना है कि प्रशासन अब तक का सबसे पारदर्शी रहा है और पीड़ितों के हित में काम कर रहा हैं।

डेमोक्रेट सांसदों ने आरोप लगाया है कि फाइलों को अधूरा जारी कर कानून की भावना का उल्लंघन किया गया। सीनेट और हाउस की कई समितियों ने चेतावनी दी है कि अगर पूरी जानकारी सामने नहीं लाई गई, तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता हैं। न्याय विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और दस्तावेज जारी किए जाएंगे, लेकिन तब तक यह सवाल बना हुआ है कि एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़ी पूरी सच्चाई कब और कितनी सामने आ पाएगी।

सैलरी, इंश्योरेंस से लेकर पेंशन तक, 7वें आयोग के 10 साल में क्या-क्या बदला?

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अहम दौर शुरू होने जा रहा है। आठ दिन बाद, यानी 31 दिसंबर को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसने पिछले 10 साल में सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर भत्तों और पेंशन तक कई बड़े बदलाव किए। न्यूनतम वेतन तय करने से लेकर फिटमेंट फैक्टर, HRA, ग्रेच्युटी और MACP जैसे नियमों ने करोड़ों कर्मचारियों की आमदनी और भविष्य की प्लानिंग को सीधे प्रभावित किया। अब सबकी नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और पेंशनर्स को क्या राहत मिलेगी? ये सवाल इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि इसका असर 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सातवां वेतन आयोग के लागू होने के बाद पिछले 10 साल में क्या-क्या बदला? और आठवें वेतन आयोग से क्या-क्या उम्मीदें हैं? चलिए समझते हैं।

1. **लागू होने की तारीख:** 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इसी आधार पर सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव हुए।
2. **न्यूनतम वेतन:** एक्रोयड फॉर्मूला के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह तय किया गया।
3. **अधिकतम वेतन:** एपेक्स स्केल के अधिकारियों का अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपए प्रति माह और कैबिनेट सचिव व समान स्तर के अधिकारियों का वेतन 2.50 लाख रुपए प्रति माह तय हुआ।

जैकब डफी की घातक गेंदबाजी पर अश्विन हुए मुरीद, तोड़ा रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड

(एजेन्सी)।

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए आखिरी टेस्ट के बाद चर्चा का केंद्र जैकब डफी बने हुए हैं और अब उनकी तारीफ भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी खुलकर की। मुकाबले के पांचवें दिन डफी की घातक गेंदबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और न्यूजीलैंड को तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से जीत दिलाई। बता दें कि माउंट माउंगानुई में खेले गए इस टेस्ट में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 462 रनों का असंभव लक्ष्य मिला था। जवाब में पूरी टीम 138 रन पर ढेर हो गई। इस पारी में जैकब डफी ने 5 विकेट देकर सिर्फ 42 रन खर्च किए और कैरेबियाई बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। गौरतलब है कि यह इस सीरीज में डफी का तीसरा पांच विकेट हॉल रहा।

मौजूद जानकारी के अनुसार, इस प्रदर्शन के साथ ही डफी ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में न्यूजीलैंड के महान गेंदबाज रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डफी ने 2025 में अब तक 81 अंतरराष्ट्रीय विकेट झटके हैं, जबकि हेडली के नाम यह आंकड़ा 80 का था। पूरी सीरीज में डफी ने 23 विकेट लिए, जो न्यूजीलैंड के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की शानदार शुरूआत मानी जा रही है।

मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर डफी की जमकर सराहना की। उन्होंने लिखा कि 2025 डफी के करियर का सबसे बड़ा साल साबित हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत, स्ट्राइक रेट और मैन ऑफ द सीरीज का प्रदर्शन काबिले-तारीफ है। अश्विन ने यह भी याद दिलाया कि डफी मौजूदा समय में टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज हैं और इस साल उन्होंने टी20 में भी 50 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। अश्विन के मुताबिक 31 साल की उम्र में डफी अपने करियर के शिखर पर खेल रहे हैं और आईपीएल में आरसीबी द्वारा उन्हें बेस प्राइस पर खरीदना एक शानदार सौदा साबित हो सकता है।

पांचवें दिन की बात करें तो सुबह मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन डफी ने नई गेंद से आते ही आक्रमण किया। उन्होंने पहले वेस्टइंडीज के टॉप स्कोरर ब्रैंडन किंग को आउट किया और फिर एथनाज, जस्टिन ग्रीव्स और कप्तान रोस्टन चेज को बेहद कम रन पर पवेलियन भेज दिया। आखिरी विकेट भी डफी ने ही लिया और न्यूजीलैंड ने 323 रन की बड़ी जीत दर्ज की।

शिल्पा शेट्टी ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की जमकर तारीफ

(एजेन्सी)। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ़्ते में भी जबरदस्त कमाई कर रही है। तीसरे हफ़्ते में इसे जेम्स कैमरन की अवतारः फायर एंड ऐश से टक्कर मिली, फिर भी इसने भारत और विदेशों दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर के कलाकारों की जमकर सराहना करते हुए इसे देशभक्ति की भावना से लैस सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है। धुरंधर पांच दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर. माधवन और राकेश बेदी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी कंधार विमान अपहरण, 2001 संसद हमला और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों जैसी भू-राजनीतिक तथा आतंकवादी घटनाओं की पृष्ठभूमि में खुफिया एजेंसियों के गुप्त अभियानों पर आधारित है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर सोमवार को एक वीडियो साझा किया जिसमें वह फिल्म के गीत एफए9एलए के चर्चित स्टेप (नृत्य) को करती नजर आ रही हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना पर फिलमाया गया यह स्टेप काफी चर्चा में है।

चाइल्ड काउंसलर बनकर संवारें अपना भविष्य

एक चाइल्ड काउंसलर के पास संभावनाओं की कमी नहीं है। वह स्कूल से लेकर हॉस्पिटल्स तक में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न एनजीओ व बच्चों के लिए काम कर रही संस्थाओं में उनकी आवश्यकता होती है। वहीं आप स्पेशल स्कूल्स या बाल सुधार गृह में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं।

आज के तनावपूर्ण जीवन में सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चे भी कई तरह की परेशानियों जैसे माता-पिता व अन्य लोगों से रिश्ते, एग्जाम प्रेशर व पीयर प्रेशर आदि से दो-चार होते हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करते और कई बार तो अपनी परेशानियों को मन में ही रखने के कारण वह अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में उनकी परेशानियों को समझकर उन्हें अंधेरे से निकालकर उजाले में लाने का काम करते है चाइल्ड काउंसलर। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर व्यक्ति को दूसरों की सहायता करके एक अजीब सी संतुष्टि का अनुभव होता है।

क्या होता है काम

एक चाइल्ड काउंसलर बच्चों के व्यवहार और भावनात्मक मुद्दों पर उनकी सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही वह बच्चों के डेवलपमेंट मुद्दों जैसे चिंता, नींद, पर्सनैलिटी डिसआर्डर व ईटिंग डिसआर्डर को भी दूर करते हैं। उनका मुख्य काम पहले बच्चों के साथ एक रिश्ता विकसित करना होता है ताकि वह अपने मन की उन बातों को भी साझा करें, जिसे वह किसी से भी नहीं कह पाते। इसके बाद वह उनकी बातों को सुनकर व उसके हाव-भावों के जरिए उसके मन की परेशानी को गहराई से समझते हैं। वह न सिर्फ बच्चों को काउंसिल करता है, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पैरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं। जिससे माता-पिता बच्चों के मन की बात समझकर उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकें।

स्किल्स

जो लोग एक सफल चाइल्ड काउंसलर बनना चाहते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स व इंटरपर्सनल स्किल्स काफी अच्छे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें बच्चे को आसानी से सहज करने व बेहतरीन तालमेल बिठाने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सच में एक बेहतरीन चाइल्ड काउंसलर बनने की इच्छा रखते हैं तो आपको तटस्थ व निष्पक्ष होकर बच्चे की बातों को सुनना व समझना चाहिए। अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों या माता-पिता को महज इसलिए अपनी बात नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनकी बात नहीं समझेंगे या फिर उन्हें गलत समझेंगे। ऐसा अनुभव उन्हें चाइल्ड काउंसलर की बातों से नहीं होना चाहिए। आपके भीतर यह क्षमता होनी चाहिए कि आप बच्चों को यह विश्वास दिला सके कि आप उनकी बातों को सुनेंगे, जज नहीं करेंगे।

योग्यता

इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए 12वीं के बाद साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद आप साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस व काउंसिलिंग कर सकते है। इसके बाद एमफिल या पीएचडी भी की जा सकती है।

संभावनाएं

एक चाइल्ड काउंसलर के पास संभावनाओं की कमी नहीं है। वह स्कूल से लेकर हॉस्पिटल्स तक में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न एनजीओ व बच्चों के लिए काम कर रही संस्थाओं में उनकी आवश्यकता होती है। वहीं आप स्पेशल स्कूल्स या बाल सुधार गृह में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वहीं आप खुद का सेंटर भी खोलकर काम कर सकते हैं।

आमदनी

अगर वेतन की बात की जाए तो इसमें सैलरी से अधिक मानसिक संतुष्टि को महत्व दिया जाता है। वहीं एक स्कूल में नियुक्त काउंसलर 15000 से 20000 रूपए प्रतिमाह कमा सकता है। वहीं एक अनुभवी चाइल्ड काउंसलर की सैलरी एक बड़े स्कूल में 25000 से 30000 तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी प्रतिष्ठित प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 30000 या उससे अधिक हो सकती है।

प्रमुख संस्थान

दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली
अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली
पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ काउंसिलिंग, नई दिल्ली

नैनोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी के अवसर और स्कोप

नैनोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच होती है। यह अत्यंत छोटी चीजों के अध्ययन से संबंधित है और इसका उपयोग अन्य सभी विज्ञान क्षेत्रों, जैसे कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में किया जा सकता है।

नैनोटेक्नोलॉजी क्या होती है?

नैनोटेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह फील्ड है जिसमें नैनोकणों और सामग्रियों को विकसित किया जाता है, जिनका आकार नैनोमीटर की सीमा के भीतर होता है। नैनोटेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो लगभग हर तकनीकी अनुशासन – रसायन विज्ञान से लेकर कंप्यूटर विज्ञान तक – अत्यंत सूक्ष्म सामग्रियों के अध्ययन और अनुप्रयोग में संलग्न है। यह अकादमिक और शोध से संबंधित शीर्ष रैंक वाले विषयों में से एक है। नैनोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच होती है। यह अत्यंत छोटी चीजों के अध्ययन से संबंधित है और इसका उपयोग अन्य सभी विज्ञान क्षेत्रों, जैसे कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में किया जा सकता है। यह हमारे जीवन में क्रांति लाने और कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और चिकित्सा में हमारी समस्याओं के तकनीकी समाधान प्रदान करने की विशाल क्षमता के साथ अनुसंधान के क्षेत्र का तेजी से विस्तार कर रहा है।

मास्टर पाठ्यक्रम

नैनोटेक्नोलॉजी में एमएससी
नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमएससी
नैनोटेक्नोलॉजी में एमटेक
सामग्री विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में एमटेक
नैनो प्रौद्योगिकी और नैनो सामग्री में एमटेक

डॉक्टरेट पाठ्यक्रम

नैनोटेक्नोलॉजी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

नैनोटेक्नोलॉजी डिग्री क्या है?

यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और आणविक जीव विज्ञान के साथ एक बहु-विषयक प्राकृतिक विज्ञान पाठ्यक्रम है।

पाठ्यक्रम और पात्रता

नैनोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर और डॉक्टरेट स्तर पर प्रदान की जाती है। भारत में कोई भी संस्थान नैनोटेक्नोलॉजी में स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करता है। मैटेरियल साइंस, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में बीटेक डिग्री या भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीवन विज्ञान में बीएससी रखने वाले उम्मीदवार नैनो टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नैनोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीवन विज्ञान में बीएससी या सामग्री विज्ञान / यांत्रिक / जैव चिकित्सा / रसायन / जैव प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक उत्तीर्ण होना चाहिए।

पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आदि में एमटेक या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आदि में एम.एससी पास होना चाहिए। उम्मीदवार 5 साल की अवधि के लिए नैनो टेक्नोलॉजी (डुअल डिग्री) में बीटेक + एमटेक भी चुन सकते हैं।

नैनोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है?

आने वाली पीढ़ियों में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। आईटी और इंटरनेट की तुलना में यह तीसरा सबसे अधिक फलता-फूलता क्षेत्र है। भारत में बैंगलोर और चेन्नई आईटी और मेडिसिन के विनिर्माण केंद्र हैं। भारत सरकार ने पहले ही नैनोसाइंस और नैनो टेक्नोलॉजी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जैसी विभिन्न फंडिंग एजेंसियों को शुरू कर दिया है।

नैनोटेक्नोलॉजी के लिए करियर विकल्प क्या हैं?

नैनोटेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ या वैज्ञानिकके के रूप में नौकरी मिल सकती है। जिन क्षेत्रों में नैनोटेक्नोलॉजिस्ट रोजगार की तलाश कर सकते हैं उनमें जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, भोजन, आनुवंशिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, चिकित्सा आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आदि में भी नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। पीएचडी वाले उम्मीदवार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों या अनुसंधान क्षेत्रों में संकाय सदस्यों के रूप में भी शामिल हो सकते हैं।

नैनोटेक्नोलॉजी में जॉब रोल्स क्या हैं?

नैनोटेक्नोलॉजिस्ट
वैज्ञानिक
शोधकर्ता
प्रोफेसर
खाद्य वैज्ञानिक
इंजीनियर चिकित्सा वैज्ञानिक

उद्योग / कंपनियां / जो इन पेशेवरों को नियुक्त करते हैं:

इलेक्ट्रॉनिक्स / सेमीकंडक्टर उद्योग
विनिर्माण उदयोग
जैव प्रौद्योगिकी
दवाइयों
चिकित्सा क्षेत्र
पर्यावरण
विश्वविद्यालयों
उत्पाद आधारित कंपनियां (खाद्य)
अनुसंधान प्रयोगशाला

वेतन

फ्रेशर के लिए लगभग 20,000/- से 30,000 रुपये प्रति माह और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपये प्रति माह के वेतन की उम्मीद की जा सकती है।

नैनोटेक्नोलॉजी ऑफर करने वाले भारत के शीर्ष कॉलेज:

भौतिकी विभाग, आईआईएससी, बैंगलोर
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल, एनआईटी, कालीकट
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो-टेक्नोलॉजी, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा

सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सेक्रेटरी से मैनेजर तक

सेकेट्रेरियल प्रैक्टिस या ऑफिस मैनेजमेंट और पर्सनल सेकेट्रेरियल प्रैक्टिस कोर्स करके आप महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के पर्सनल सेक्रेटरी बनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अनेक शॉर्ट टर्म और डिग्री कोर्स उपलब्ध हैं।

वैश्वीकरण के बाद जिस तेजी से ऑफिस की कार्यप्रणाली और स्वरूप बदला है, ऑफिस सेकेट्ररी और पर्सनल सेक्रेटरी की भूमिका भी अहम होती जा रही है। सेकेट्रेरियल प्रैक्टिस या ऑफिस मैनेजमेंट और पर्सनल सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कोर्स में दाखिला लेकर आप ऑफिस सेकेट्ररी या पर्सनल सेकेट्ररी बन कर एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ऑफिस सेकेट्ररी किसी ऑफिस में प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रमों को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाता है। महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों के पर्सनल सेक्रेटरी बन कर आप उनके डेली रूटीन तथा ऑफिस शड्यूल को मैनेज करते हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालय और प्राइवेट संस्थान सेकेट्रेरियल प्रैक्टिस या ऑफिस मैनेजमेंट और सेकेट्रेरियल प्रैक्टिस में शॉर्ट टर्म डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्स ऑफर करते हैं।

योग्यता तथा पढ़ाई

शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रवेश लेने के लिए दसवीं तथा कुछ संस्थानों के लिए बारहवीं पास होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में आगे की पढ़ाई मसलन डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स करने के लिए बारहवीं पास होना अनिवार्य योग्यता है। इन कोर्सों के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना अतिआवश्यक है। इन कोर्सों का मुख्य उद्देश्य छात्र को सेक्रेटरी के उत्तरदायित्वों को समझाना, सेक्रेटेरियल कार्यों के लिए गुणों का विकास करना, संगठन या ऑफिस की कार्यप्रणाली को समझाना तथा कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स आदि ऑफिस में प्रयोग होने वाले उपकरणों को ऑपरेट करना सिखाया जाता है। शॉर्ट टर्म कोर्स में शॉर्ट हैंड, टाइपराइटिंग, कंप्यूटर बेसिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन तथा पर्सनेलिटी डेवलपमेंट विषय पढ़ाए जाते हैं। लेकिन डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्सों में इन विषयों के अलावा मैनेजमेंट, अकाउंट, कंपनी लॉ और बैंकिंग सर्विसेज विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है।

संभावनाएं

कोर्स करने के बाद सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्रों में सभी तरह के दफ्तरों में सेक्रेटरी की जॉब मिलती है। लेकिन हाल में मल्टीनेशनल, पब्लिक सेक्टर कंपनियों तथा होटल्स में स्किल्ड सेकेट्ररी और ऑफिस सेकेट्ररी के जॉब की अपार संभावनाएं हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों, लॉजिस्टिक फर्म तथा ट्रैवल एजेंसी में भी सेक्रेटरी के रूप में जॉब कर सकते हैं। अपनी योग्यता तथा अनुभव से आप सेक्रेटरी से जॉब शुरू करके ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं।

संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे जगद् गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

गांव चुहड़ माजरा का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा करने सहित कई घोषणाएं कर मुख्यमंत्री ने खोला सौगातों का पिटारा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

ढांड/कैथल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहा कि जगद् गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे। उनका पूरा जीवन मानव सेवा, धर्म, त्याग और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा। वे ऐसे प्रकाशस्तंभ थे, जिनके ज्ञान की किरणें आज भी हमारे विचारों, हमारी संस्कृति और समाज को दिशा प्रदान कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गांव चुहड़ माजरा का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा करने की आधिकारिक घोषणा की। साथ ही उन्होंने कई बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा कर विकास का पिटारा खोल दिया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को कैथल जिले के गांव चुहड़ माजरा में हरियाणा सरकार द्वारा जगत गुरु ब्रह्मानंद जी जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने की। समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्ढा, कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा, श्री महीपाल ढांडा, राव नरबीर सिंह, सांसद श्री नवीन जिंदल एवं विधायक श्री सतपाल जांबा सहित, राम

कुमार कश्यप, योगेंद्र राणा, भगवानदास कबीरपंथी अन्य विधायकगण व पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक सहित समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव चुहड़ माजरा में पहुंचने पर सबसे पहले गांव में गुरु ब्रह्मानंद मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की। इसके बाद सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से गुरु ब्रह्मानंद जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में अपने संदेश में महान संत स्वामी ब्रह्मानंद जी को नमन करते हुए कहा कि गुरु ब्रह्मानंद जी ने समाज को ज्ञान, भक्ति और समरसता का मार्ग दिखाया था। सादा जीवन उच्च विचार उनके मुख्य संस्कार थे। उनका जन्म वर्ष 1908 में हरियाणा के कैथल जिले के चुहड़ माजरा गांव में एक साधारण रोड परिवार में हुआ। बचपन से ही ईश्वर-भक्ति का गहरा रुझान, अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा और परमात्मा की खोज की धुन उन्हें अलग पहचान देती थी। उन्होंने अपना जीवन, कर्म, ज्ञान व तपस्या मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी जी का आर्य समाज में गहरा विश्वास था। वे एकेश्वरवाद, ओंकार और निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश देते थे। उनका कहना था कि ईश्वर सबका है, सबके लिए है और मानवमात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर-भक्ति है। उनका जीवन इस सत्य का ज्वलंत उदाहरण था। जब समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम सुविधाओं का अभाव था और समाज को रूढ़िवादिता ने घेरा हुआ था, उस समय में गुरु ब्रह्मानंद जी ने अपनी वाणी, अपनी कलम और अपने कर्म से समाज में जागरूकता की नई अलख जगाई। उन्होंने उस समय में ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर महिलाओं में शिक्षा प्रसार को अपना ध्येय बनाया। उनका विश्वास था कि गौ सेवा, शिक्षा और समाज सुधार, इन तीन स्तंभों पर ही एक सुखी और सभ्य समाज की नींव टिक सकती है।

स्वामी ब्रह्मानन्द जी का जीवन हमें हमारी महान भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे नैतिक मूल्यों की रक्षा और संवर्धन की प्रेरणा देता है। आज के सामाजिक माहौल में स्वामी जी के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। हमारा दायित्व है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में नैतिकता, सामाजिक मूल्यों और आपसी सद्भाव की कड़ियों को मजबूत करें। यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके समाज सुधार, शिक्षा प्रसार और गौ सेवा जैसे पवित्र कार्यों को आगे बढ़ाएं और उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने की गेट मीटिंग

संजना भारती संवाददाता

असंध। आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन असंध यूनिट की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने सब यूनिट स्तर पर तीन घंटे तक सांकेतिक भूख हड़ताल भी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता दोनों सब यूनिट के प्रधान अजमेर जागलान व अजीत रेढू ने संयुक्त रूप से की। मंच का संचालन कृष्ण पाई ने किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से राज्य कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र पाल ने शिरकत की।

गेट मीटिंग के दौरान बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को कर्मचारी विरोधी बताया। बिजली कर्मचारियों ने एसडीओ के माध्यम से बिजली मंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्य कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र पाल ने कहा कि बिजली कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह नीति कर्मचारियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब किसी तकनीकी कर्मचारी का नई जगह तबादला किया जाता है तो उसे वहां की बिजली लाइनों, फीडरों और तकनीकी व्यवस्थाओं को समझने में समय लगता है। इस दौरान कर्मचारी हादसे का शिकार भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद किया जाए। यूनिट प्रधान नरेन्द्र पहल ने सरकार को चेताया यदि सरकार ने समय इस तबादला नीति को बंद नहीं किया तो यूनियन आन्दोलन तेज करने पर मजबूर होगी।

इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान कैलाश शर्मा, बिजेंद्र जसवाल, रामबीर मोर, संजय वर्मा, सोनिया, सविता, अंजू, सुनिता, सतीश बल्ला, साहिल, संदीप उपलाना, राहुल जांगड़ा, प्रदीप आदि मौजूद रहे।

लिंगानुपात में सुधार के लिए लोगों को जागरूक करने के दिए निर्देश

एसबी संवाददाता

असंध। करनाल की सिविल सर्जन डा. पूनम चौधरी ने बीडीपीओ कार्यालय सभागार में असन्ध के सभी सीएचओ, एमपीएचएस व एमपीएचडब्ल्यू के साथ बैठक कर टीकाकरण, लिंगानुपात, टीबी व एनसीडी आदि विषयों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए।

बैठक के दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि लिगांनुपात में सुधार के लिए फील्ड स्टाफ के द्वारा अधिकाधिक लोगों को जागरुक किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर भी पंचायतों व अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएं ताकि क्षेत्र के लिंगानुपात में और सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं द्वारा एएनएम के पास जल्द पंजीकरण कराया जाए व लड़के व लड़की में भेदभाव न किया जाए। यदि कोई व्यक्ति प्रसव पूर्व लिंग जांच की सूचना विभाग को देता है तो उसे एक लाख रुपये इनाम दिया जाएगा व उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। सिविल सर्जन ने टीकाकरण कार्यक्रम को भी सुचारु रुप से चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने टीबी से संबंधित कार्यक्रम को भी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए और बताया कि बिलगम जांच एक हजार की जनसंख्या पर 60 व्यक्तियों की होनी चाहिये, जो पहले 30 व्यक्तियों की होती थी। इसके बाद उन्होंने एनसीडी कार्यक्रम के तहत भी 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की शुगर व बी.पी की जांच करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि शुगर व बीपी के जो भी मरीज पाये जाते है, उनका उपचार शुरू किया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सूबे सिंह, उपसिविल सर्जन करनाल डॉ. रवींद्र संधू, दंत चिकित्सक डॉ.यशपाल, डॉ. विभूति आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय किसान दिवस पर करनाल में विकसित भारत-जी राम जी योजना पर केंद्रित कार्यक्रम

भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान में 150 से अधिक किसानों की भागीदारी

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर भाकृअनुप-भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल में राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं हरियाणा से आए 150 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-जी राम जी योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों और श्रमिकों के लिए बेहतर बेरोजगारी भत्ता, समय पर मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी होने पर मुआवजा, ग्राम सभा द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना तथा 125 दिन की रोजगार गारंटी जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने इसे ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल बताया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तकनीक के माध्यम से किसानों और श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा, जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कार्यक्रम को रेखांकित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपमहानिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट ने सभी अनुसंधान संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि गेहूँ और जौ जैसी प्रमुख फसलों की उन्नत किस्मों के विकास, नवीन तकनीकों के प्रसार तथा सतत उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए संस्थान निरंतर प्रयासरत है।

इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूँ व जौ की नवीनतम किस्मों, समन्वित फसल प्रबंधन, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य एवं जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों पर व्याख्यान दिए। साथ ही किसानों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं नवाचार के लिए 30 महिला एवं पुरुष किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में किसानों के हित में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लिया गया।

भौतिकवाद के युग में भी प्रासंगिक हैं जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी के विचार: शक्ति सिंह

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। महान तपस्वी, वैदिक धर्म के प्रखर प्रचारक, समाज सुधारक एवं यज्ञ सम्राट जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी का जीवन त्याग, सेवा और सत्य की साधना का अनुपम उदाहरण है। उनके विचार आज के भौतिकवाद के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं और समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। यह विचार प्रेरक वक्ता एवं समाजसेवी एडवोकेट चौधरी शक्ति सिंह ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी गरीबों के मसीहा, महिलाओं के उत्थानकर्ता और वैदिक ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे। हरियाणा सरकार द्वारा स्वामी जी की 118वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव चुहड़माजरा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर उनकी शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार किया गया, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म 24 दिसंबर 1908 को कैथल जिले के चुहड़माजरा गांव में हुआ। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने गुरुकुल में हिंदी एवं संस्कृत का गहन अध्ययन किया और ब्रह्मज्ञान की खोज में कठोर तपस्या की। ओमपुरा गुरुकुल की स्थापना कर उन्होंने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सेवा और वैदिक ज्ञान के पांच सिद्धांत प्रतिपादित किए।

स्वामी जी ने जीवनभर वैदिक धर्म का प्रचार किया और असंख्य हवन-यज्ञों का आयोजन कर समाज को संस्कारों से जोड़ा। उन्होंने महिलाओं को वैदिक शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया तथा गरीबों और असहायों की सेवा को सर्वोपरि रखा। 16 मई 1973 को वे ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी देश-विदेश में आश्रमों और सत्संगों के माध्यम से जन-जन को प्रेरित कर रही हैं।

किसान एवं कृषि विकास से चौधरी चरण सिंह का सपना साकार: केंद्रीय कृषि मंत्री

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-एनडीआरआई), करनाल में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निदेशक एवं कुलपति डॉ. धीर सिंह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जलवायु समुत्थानशील कृषि योजना, फसल अवशेष प्रबंधन, प्राकृतिक खेती किसान उत्पाद समूह, स्वयं सहायता समूह, ड्रोन दीदी, हरियाणा विज्ञान मंच सहित संस्थान के संकाय सदस्य, छात्र, अधिकारी एवं कर्मचारी मिलाकर लगभग 390 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों, 113 आईसीएआर संस्थानों एवं 75 कृषि विश्वविद्यालयों से वर्चुअल रूप से जुड़े मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी किसान एवं कृषि विकास के सच्चे समर्थक थे। उन्होंने सामूहिक खेती के प्रस्ताव का विरोध कर किसानों को उनकी खेती का मालिकाना अधिकार दिलाया। श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार खेती में निवेश और निर्यात को बढ़ावा दे रही है तथा फसलवार एवं राज्यवार रोडमैप बनाकर कृषि को विशिष्टता की ओर ले जाया जा रहा है। उन्होंने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की जानकारी देते हुए बताया कि अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाकर कृषि मौसम में भी कार्य के अवसर उपलब्ध होंगे।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह दूरदर्शी और ईमानदार नेता थे, जिन्होंने भूमि सुधार, चकबंदी, सिंचाई व्यवस्था तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे ऐतिहासिक निर्णय लेकर किसानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा में वीबी-जी राम जी योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में किसानों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया।

संस्थान के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने किसानों से नवोन्मेषी तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया और उनकी समस्याओं पर वैज्ञानिक समाधान सुझाए। कार्यक्रम के दौरान करनाल जिले के प्रगतिशील महिला एवं पुरुष किसानों को उनके उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद एवं सहयोग को और सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ हुआ।

सबका साथ सबका विकास की नीति को बढ़ा रहे आगे: जगमोहन आनंद

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि सरकार ने पिछले दो कार्यकाल मे सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम किया है। वर्तमान मे भी जन प्रतिनिधि इसी नीति को आगे बढ़ा रहे है। गांव और शहर का एक समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। विधायक जगमोहन आनंद मंगलवार को गाँव काछवा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं शुभारम्भ करने उपरांत उपस्थितजनों को सम्बोधित कर रहे थे।

विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सबका साथ सबका विकास की नीति का संकल्प लिया है। वर्तमान मे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सभी मंत्री, विधायक व जन प्रतिनिधि इसी सोच को आगे बढ़ा रहे है।

एक करोड़ तीस लाख की लागत से गुगामाड़ी से लेकर स्टेडियम तक सड़क का निर्माण, लगभग 75 लाख की लागत से गुरुद्वारा बहलोलपुर रोड तक फिरनी के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास, 10 लाख की राशि से रायफार्म में बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास, 15 लाख से बनी कश्यप चौपाल का उद्घाटन, 25 लाख की लागत से बनने वाली हरिजन चौपाल के निर्माण का शिलान्यास, 10 लाख की लागत से खेड़े के नजदीक सामुदायिक हॉल को पूर्ण करने हेतु कार्य का शिलान्यास, 10 लाख की लागत से रोड़ चौपाल के प्रथम तल के निर्माण कार्य का शिलान्यास, 15 लाख की राशि से सुनार चौपाल का उद्घाटन,10 लाख की लागत से रायसिख चौपाल के निर्माण कार्य का शिलान्यास, 10 लाख की लागत से ओढ़ चौपाल के निर्माण कार्य का शिलान्यास, 10 लाख की लागत से गोगामाढ़ी की चारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास, भट्ट चौपाल का नवीनीकरण, वाल्मीकि चौपाल का नवीनीकरण।

इस अवसर पर सरपंच सुशीला देवी, सरपंच प्रतिनिधि दीपक कुमार, मंडल महामंत्री बंसी लाल कलामपुरा, पूर्व सरपंच बिट्टू, जोगिंदर सिंह, राजबीर खोखर कलामपुरा, देवेंद्र गुर्जर पुण्डरक, गुरमीत बाजीगर, प्रदीप भाटिया, पालेराम धनखड़, निशांत शर्मा शानू सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं परिवारजन उपस्थित रहे।

करनाल में नव नियुक्त एसडीएम प्रदीप कुमार ने संभाला कार्यभार

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। करनाल के नव नियुक्त उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) प्रदीप कुमार ने सोमवार को औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेकर प्रशासनिक कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तत्परता से करने का आह्वान किया। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके बाद एसडीएम ने सरल केंद्र का निरीक्षण कर वहां आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और फाइलों को बेवजह लंबित न रखा जाए।

एसडीएम प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जाए।

शहीदी सभा: फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने वाली संगतों की सुविधा के लिए 3400 पुलिस कर्मी, 22 पार्किंग स्थल, शटल बसें

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा/चंडीगढ़/फतेहगढ़ साहिब। शहीदी सभा के मद्देनजर पुलिस के विशेष डायरेक्टर जनरल (स्पेशल डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने आज फतेहगढ़ साहिब का दौरा किया और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया ताकि जिले में सुचारू और सुरक्षित ढंग से समागम सुनिश्चित किया जा सके। दसवें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों-बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, की अद्वितीय शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए तीन दिवसीय वार्षिक शहीदी सभा 25 दिसंबर से 27 दिसंबर, 2025 तक फतेहगढ़ साहिब में होगी। उल्लेखनीय है कि पूरे क्षेत्र को योजनाबद्ध ढंग से छह सेक्टरों में विभाजित किया गया है और दुनिया भर से आने वाली लाखों संगतों की सुरक्षा, सुचारू आवागमन तथा आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए छह एसपी रैंक के अधिकारियों एवं 24 डीएसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में 3400 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली फोर्स तैनात की गई है। विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला, जिनके साथ डीआईजी रोपड़ रेंज नानक सिंह तथा एसएसपी फतेहगढ़ साहिब शुभम अग्रवाल भी मौजूद थे, ने शहीदी सभा के पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए तैनात एसपी एवं डीएसपी रैंक के सभी अधिकारियों तथा पुलिस फोर्स को लगन से सेवा निभाने की हिदायत दी।

सरकारी निशानदेही के दौरान कनिष्ठ अभियंता से मारपीट, जान से मारने की धमकी का आरोप

राजौंद नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता ने थाना राजौंद में दी शिकायत, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग

एसबी संवाददाता

राजौंद। नगरपालिका राजौंद में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता अश्वनी कुमार के साथ सरकारी कार्य के दौरान मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता ने थाना प्रबंधक राजौंद को लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत पत्र के अनुसार, कनिष्ठ अभियंता अश्वनी कुमार 23 दिसंबर 2025 को खसरा नंबर 524, वार्ड नंबर 01 में नगर पालिका राजौंद की ओर से निशानदेही के सरकारी कार्य में शामिल थे। इस कार्य के दौरान उनके साथ कानूनगो श्री जगर सिंह, पटवारी श्री सत्यदेव तथा नगर पालिका के दो सफाई कर्मचारी राजेंद्र व संजय भी मौके पर मौजूद थे। निशानदेही का कार्य शांतिपूर्वक चल रहा था। इसी दौरान अचानक वार्ड नंबर 10 से पार्षद प्रतिनिधि व उपप्रधान का पुत्र मनजीत राणा, पार्षद विकास राणा सहित अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कनिष्ठ अभियंता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हाथापाई शुरू कर दी और थप्पड़ मारे। शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

कनिष्ठ अभियंता ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना के कारण सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई और निशानदेही का कार्य बीच में ही रोकना पड़ा। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारियों में रोष का माहौल है और कर्मचारियों ने इसे सरकारी कार्य में सीधा हस्तक्षेप बताया है।

कनिष्ठ अभियंता अश्वनी कुमार ने पुलिस प्रशासन राजौंद, नपा सचिव राजौंद, उपायुक्त कैथल, पूलिस अधिक्षक कैथल को लिखित शिकायत दे कर अनुरोध किया है कि उनके साथ हुई मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस शिकायत की प्रतिलिपि उपायुक्त कैथल, पुलिस अधीक्षक कैथल, जिला नगर आयुक्त कैथल तथा नगर पालिका राजौंद के सचिव को भी भेजी गई है।

मामले को लेकर पुलिस द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने और जांच के बाद उचित कार्रवाई किए जाने की संभावना जताई जा रही है। घटना ने नगर पालिका कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।